भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1812
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: बिहार में कृषि अनुसंधान

1812. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्वी भारत के लिए घोषित पूर्वोदय योजना के तहत विहार राज्य में सतत कृषि, उत्पादकता वृद्धि और अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2023 से उक्त योजना के तहत बिहार के लिए आवंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इससे क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार स्वीकार करती है कि बिहार में कृषि अनुसंधान के परिणाम प्रभावी रूप से किसानों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोदय योजना के तहत औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार सेवाओं का कोई अलग से आकलन किया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) सरकार बिहार राज्य सहित पूरे देश में सतत कृषि पद्धतियों और उत्पादकता वृद्धि को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) लागू कर रही है।

(ख) बिहार राज्य में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एनएमएसए के अंतर्गत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाना है। अब तक 233.75 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और राज्य में पीडीएमसी के अंतर्गत 35496 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना 2014-15 में शुरू की गई थी, जो उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। अब तक 2024.74 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं और राज्य में 3519 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) को वर्ष 2014-15 में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अब तक 8440.87 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं और राज्य में 15653800 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) बिहार में 2005-06 से लागू किया गया था। अप्रैल 2014 से, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एनएचएम को समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब तक राज्य में 34177 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों की खेती की जा चुकी है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) के तहत बिहार में 400 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें 49,855 किसान पंजीकृत हैं और 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। 31.12.2025 तक, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत बिहार में 31,783.27 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, जिससे 43,208 किसानों को लाभ मिल रहा है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत बिहार राज्य को कुल 7,244.08 लाख रुपए का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के दौरान पीकेवीवाई के अंतर्गत बिहार को ₹3,419.00 लाख का आवंटन किया गया, जिसमें से 31.12.2025 तक 1,710.00 लाख रुपए का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर (आईसीएआर-आरसीईआर) और इसके कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बक्सर बिहार के कई जिलों (बक्सर, गया, औरंगाबाद, जमुई, समस्तीपुर आदि) में अनुसंधान-किसान संबंधों को मजबूत करने के लिए विस्तार और जनसंपर्क गतिविधियाँ चला रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई प्रमुख जनसंपर्क और विस्तार गतिविधियों में क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, फील्ड डे, किसान गोष्ठी/मेला और जागरूकता एवं प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल हैं, जिनसे क्रमशः वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 9,250, 6,550 और 7,650 लाभार्थियों को लाभ मिला। पिछले तीन वर्षों में केवीके बक्सर के माध्यम से किसानों के लिए कुल 268 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 7,800 से अधिक किसानों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, चावल, दालों और अन्य फसलों की जारी की गई किस्मों के प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ बकरी पालन, एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) और फसल विविधीकरण सहित विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के तहत गतिविधियों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 7,500 किसानों को लाभ मिलता है। इस संस्थान ने अनाज और दालों के 50.0 टन गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन भी किया, जिसे विभिन्न माध्यमों से किसानों तक पहुँचाया गया। कुल मिलाकर, आईसीएआर-आरसीईआर, पटना और इसके केवीके बक्सर ने मिलकर पिछले तीन वर्षों में बिहार राज्य के लगभग 81,950 किसानों तक उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए पहुँच बनाई। आईसीएआर बिहार में बड़े पैमाने पर, डेटा-आधारित विस्तार और आउटरीच प्रयासों के माध्यम से कृषि अनुसंधान और किसानों के बीच अंतराल को पाटने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

(ग) एवं (घ) सरकार ने आईसीएआर के माध्यम से बिहार में 44 कृषि केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और राज्य सरकारों के विस्तार कार्यकर्ताओं एवं किसानों के बीच क्षमता विकास के माध्यम से राज्य के किसानों के बीच कृषि अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करना है। वर्ष 2024-25 के दौरान, इन केवीके ने उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों पर 23,181 प्रदर्शन आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, केवीके ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1.73 लाख किसानों/महिला किसानों/ग्रामीण युवाओं/विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षित किया और विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर 13.09 लाख हितधारकों को जागरूक किया। उन्नत फसल किस्मों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, इन केवीके ने 27837.95 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज और बागवानी फसलों के 24.86 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन किया।

****